



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 122-2023/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई, 2023
(21 आषाढ़, 1945 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 41/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2023, दिनांक 12 जुलाई, 2023— हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2023	493-494
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग—III**हरियाणा सरकार**

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जुलाई, 2023

संख्या का०आ० 41/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2023.— हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 209 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, इसके द्वारा उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2023, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 में, नियम 28 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“28क ग्राम निधि, समिति निधि तथा जिला परिषद् निधि का लागू होना। धारा 21, 75, 100, 137, 146 तथा 209.—(1) ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् अधिनियम द्वारा या के अधीन इसे सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपनी निधि का उपयोग इस शर्त के अधीन कर सकती है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को दिए गए सहायता अनुदान का उपयोग उस विशिष्ट प्रयोजन, यदि कोई हो, के लिए किया जाएगा, जिसके लिए वह सरकार द्वारा सौंपा गया है।

(2) सरकार, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् को अपनी निधि में से ऐसे कृत्य या कर्तव्य का पालन करने या ऐसे विकास कार्य कार्यान्वित करने के लिए निर्देश कर सकती है, जो अधिनियम द्वारा या के अधीन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् को सौंपे गए हैं, इस शर्त के अधीन कि ऐसे विकास कार्य की मांग ऐसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् के निवासियों द्वारा की गई है और सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में माना गया है।”।

अनिल मलिक,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 12th July, 2023

No. S.O. 41/H.A.11/1994/S.209/2023.— The following draft of rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department, from any person with respect to the draft of rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2023.
2. In the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, after rule 28, the following rule shall be inserted, namely:-

“28A. Application of Gram Fund, Samiti Fund and Zila Parishad Fund. Sections 21, 75, 100, 137, 146 and 209.- (1) A Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad may utilize its fund for the performance of functions and duties assigned to it by or under the Act subject to the condition that any grant-in-aid by the State Government to the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad shall be utilized for the specific purpose for which it is assigned by the State Government, if any.

(2) The Government may direct a Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad to perform such function or duty or implement such development work out of its fund as has been assigned to the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad by or under the Act subject to the condition that the demand for such development work has been raised by a resident of such Gram Panchayat, Panchayat Samiti or Zila Parishad and is deemed by the State Government to be in public interest.”.

ANIL MALIK,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayats Department.